भारतीय जनता पार्टी

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक

जून 1–2, 2008

संसदीय सौध, नई दिल्ली

<u>महंगाई पर प्रस्ताव</u>

आकाश छूती कीमतें– यूपीए सरकार का आम आदमी की जेब पर डाका

वामदलों के समर्थन से बनी यूपीए सरकार के शासन काल के चार वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। यह सरकार 'आम आदमी' के हितों की रक्षा के नारे के साथ सत्ता पर आई थी। विडंबना यह है कि सरकार की बागडोर प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह के हाथों में होने के बावजूद अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ी है और कमरतोड़ महंगाई ने 'आम आदमी' का जीवन दूभर कर दिया है। आज यूपीए सरकार का हाथ, आम आदमी के साथ ना होकर उसकी जेब में है। सन् 2004 में जब एनडीए सत्ता से च्युत हुआ और यूपीए ने सरकार की कमान संभाली थी तो देश की अर्थव्यवस्था की नींव बड़ी सुदृढ़ थी। कीमतें काबू में थीं, आवश्यक वस्तुओं का बाहुल्य था और अर्थव्यवस्था के सभी मापदंड एक उदीयमान सशक्त भारत की कहानी बयां कर रहे थे।

आज की स्थितिः मुद्रास्फीति की दर 8.1 प्रतिशत

जिस समाजवादी लीक पर चलकर भारतीय अर्थव्यवस्था कंगाली और तंगहाली के मुकाम पर जा पहुंची थी, उसे एनडीए सरकार की दूरदर्शी नीतियों के कारण मुक्ति मिली और भारतीय अर्थव्यवस्था विश्वपटल पर एक शक्ति के रूप में स्थापित हुई। श्री नरसिम्हा राव की सरकार में वित्तमंत्री होने के नाते समाजवादी बेड़ियों में जकड़ी अर्थव्यवस्था को आजाद करने का बीड़ा उठाने वाले डॉ. मनमोहन सिंह के हाथों में जब सत्ता की बागडोर आई तो सबकी यह स्वाभाविक अपेक्षा थी कि वह इसे और मजबूती और एक नए मुकाम तक पहुंचाएंगे। किंतु हुआ क्या? हताशा और निराशा।

एनडीए सरकार के समय में दूरसंचार क्रांति के क्षेत्र में क्रांति आई, उसके कारण आज हाथ–हाथ में मोबाइल फोन है। लाइसेंसी राज से निजात दिलाकर रसोई गैसे को एनडीए सरकार ने न केवल घर–घर पहुंचाया, बल्कि उसकी आपूर्ति भी मांग के साथ तुरंत हो जाती थी। आज रसोई गैस से लेकर आम आदमी के ईंधन–केरोसीन तेल के लिए पुनः किल्लत मची है। मिट्टी का तेल तो राशन की दुकानों से गायब हो गया है। रसोई गैस काले बाजार में पुनः चली गई है। और खेद की बात यह है कि गैस की इस कमी को पैदा करने में केन्द्रीय सरकार की नीतियों का योगदान है। सरकार गैस सब्सीडी को कम करने के लिए जानबूझ कर गैस का उत्पादन कम कर रही है। जीवन रक्षक और आवश्यक औषधियों के दामों में भी बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। बिजली और शिक्षा बढ़ती हुई कीमतों के कारण आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गये हैं। एनडीए के शासनकाल में दाम स्थिर थे और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ थी। आज आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं।

17 मई को समाप्त सप्ताह में महंगाई की दर (थोक मूल्य सूचकांक) 8.1 प्रतिशत दर्ज की गई, जो पिछले चार साल की सर्वाधिक है। विगत 8 मई को मुद्रा स्फीति की दर 7.61 प्रतिशत की ऊंचाई पर थी। महंगाई दर का सूचकांक प्रति सप्ताह बढ़ता ही जा रहा है, परंतु मुद्रा स्फीति का यह बढ़ता हुआ थोक मूल्य सूचकांक का आंकड़ा तो महंगाई को केवल प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। वास्तविक स्थिति तो बहुत अधिक भयावह है। आम आदमी के दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम पिछले चार सालों में 50 प्रतिशत से 120 प्रतिशत तक बढ़े हैं। गरीब, निम्न मध्यम और मध्यम वर्गों के लोगों का नित प्रतिदिन का जीवन कठिन हो गया है। यह भी खेद का विषय है कि अप्रैल, 2008 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, केन्द्रीय सरकार के आदेश के कारण उपलब्ध नहीं है। इसलिए आंकड़ों के माध्यम से महंगाई का आकलन नहीं हो पाता है।

आज महंगाई क्यों?

अवसरवादी गठबंधन से एक नकारात्मक वैचारिक प्रतिष्ठान को सीढ़ी बनाकर सत्ता में पहुंची यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री के सामने डॉ. मनमोहन सिंह 'अर्थशास्त्री' हार गया। 'न्यूनतम साझा कार्यक्रम' अर्थात् CMP के नाम पर कम्युनिस्टों ने अपना एजेंडा देश पर लाद दिया और CMP को CPM लील गया। वास्तव में वामपंथियों को महंगाई का विरोध करने का कोई नैतिक अधार नहीं है।

एनडीए के राज में जो अर्थव्यवस्था सुदृढ़ थी, वह यदि आज यूपीए के चार साल में लचर हुई है और उसके परिणामस्वरूप महंगाई दावानल की तरह फैल रही है तो इसके लिए यूपीए सरकार का कमजोर नेतृत्व और वामपंथियों की सतत् ब्लैकमेलिंग बराबर की जवाबदेह है। यूपीए सरकार का कार्यकाल आपसी झगड़ों और कम्युनिस्टों के साथ रस्साकशी के बीच गुजर रहा है। सरकार राजनीतिक वैरशोधन में भी समय और संसाधन व्यर्थ खर्च कर रही है।

यूपीए सरकार अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए एनडीए पर महंगाई को लेकर राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा एक बयान जारी कर राजनीतिक दलों से जनता की मजबूरी का राजनीतिकरण नहीं करने की अपील की गई। सरकार क्या चाहती है? आम आदमी महंगाई से पिसता रहे और विपक्षी दल सत्तारुढ़ दल की तरह मस्त रहे? यदि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो लोकतंत्र में विपक्ष का अर्थ ही क्या रह जाता है?

एनडीए पर दोषारोपण

बेकाबू महंगाई के लिए सरकार हास्यास्पद तरीके से अपना दामन बचाने में लगी है। पहले तो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने झूठ बोला कि राजग सरकार की नीतियों के कारण विकास की गति धीमी रही और कीमतें बढ़ रही हैं। किंतु एक प्रधानमंत्री के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह बेकाबू महंगाई के लिए राजग सरकार की नीतियों को कसूरवार ठहराते हैं तो इतना तय है कि उनके अर्थशास्त्री स्वरूप पर क्षुद्र राजनीति से प्रेरित डॉ. मनमोहन सिंह हावी हैं। सन् 2004 में सत्ता में आने के बाद उनकी ही सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों ने उन्हें झूठा साबित कर दिया।

आर्थिक सर्वेक्षण, 2003–04 (जो वित्तमंत्री चिदंबरम ने संसद में प्रस्तुत किया) के अनुसार :

''संवृद्धि, मुद्रास्फीति तथा भुगतान संतुलन के अर्थ में अर्थव्यवस्था समुत्थानशील प्रतीत होती है, एक ऐसी संयोजन जिसमें सतत् बृहद्–आर्थिक स्थिरता के साथ संवृद्धि के संवेग के समेकन के लिए काफी गुंजायश है। सूखाग्रस्त विगत वर्ष से 9.1 प्रतिशत के सशक्त कृषिय सुधार द्वारा उत्प्लावित वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2003–04 में 8.1 प्रतिशत* की वृद्धि होने का अनुमान है। विगत में केवल तीन वर्षों में 8 प्रतिशत से उच्चतर वृद्धि प्राप्त हुई है; 1967–68 (8.1 प्रतिशत), 1975–76 (9.0 प्रतिशत) तथा 1988–89 (10.5 प्रतिशत)।"

यही आर्थिक सर्वेक्षण (2004–05) मुद्रास्फीति के बारे में कहता है:

'' थोक मूल्य सूचकांक पर बिन्दु–दर–बिन्दु वार्षिक मुद्रास्फीति दर उल्लेखनीय गिरावट के कारण वर्ष 2002–03 में 6.5 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2003–04 में 4.5 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2004–05 के दौरान 12 जून, 2004 को समाप्त सप्ताह के लिए मुद्रास्फीति दर पिछले वर्ष की असी अवधि की 5.89 प्रतिशत की तुलना में 4.97 प्रतिशत रही।''

एनडीए के समय में अर्थव्यवस्था:

श्री नरसिम्हा राव ने ऐसे समय में राजभार संभाला था, जब भारतीय अर्थव्यवस्था कंगाली के कगार पर थी। इसकी तुलना में पिछले 15 सालों से लगातार विकासमान बने रहने के कारण चीन की विकास दर 9 प्रतिशत के आंकड़े को छू रही थी। माओ के उत्तराधिकारी डेंग जियाओ पिंग द्वारा मार्क्सवाद का दामन छोड़ बाजार अर्थव्यवस्था अपनाना ही इस विकास का प्रमुख कारण था। इसलिए साठ से नब्बे के दशक तक भारत की घिसटती विकास दर के लिए कोई और नहीं, स्वयं नेहरू–गांधी कांग्रेस की तथाकथित 'समाजवादी' नीतियां ही जिम्मेवार थीं। वास्तव में कांग्रेस ब्रांड का 'समाजवाद', सरकारीकरण और भाई–भतीजावाद से उपजने वाले भ्रष्टाचार का ही दूसरा नाम था।

इसके विपरीत राजग सरकार के कार्यकाल के आंकड़े क्या बोलते हैं? अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने मार्च 1998 में कार्यभार संभाला। 1998–99 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास दर 6.5 प्रतिशत थी। अगले साल वह सरकार गिरा दी गई। उसके बाद हुए चुनाव में नए गठबंधन के साथ अटलजी की सरकार बनी। सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में नई नीतियां बनीं और उसके जो परिणाम आए, उनका पहले से कोई साम्य नहीं था। अगले चार सालों के अंत में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 8.5 प्रतिशत तक जा पहुंची।

विकास के दूसरे मापदंडों को देखें। राजग सरकार के आखिरी तीन सालों अर्थात् 2001–2002 और 2003–04 के बीच घरेलू बचत 23.5 प्रतिशत से बढ़कर 29.7 प्रतिशत हुई थी। इसी अवधि में पूंजी सृजन भी 22.9 प्रतिशत से बढ़कर 26 प्रतिशत हुआ। राजग सरकार के पूरे कार्यकाल में अर्थव्यवस्था के सारे मापदंडों में विकास दर्ज की गई। एन.डी.ए. ने देश की जनता को अभावों और ब्लैक वाली अर्थव्यवस्था से मुक्ति दिलाई थी। आज देश पुनः उस दल–दल में गिर रहा है।

सरकार के आधारहीन तर्क

सरकार समस्या का हल ढूंढ़ने की बजाए बलि का बकरा ढूंढ़ने में ज्यादा व्यस्त है। प्रधानमंत्री सहित सरकार के अन्य पैरोकार बढ़ती महंगाई के लिए राज्यों को कसूरवार बताकर एक और झूठ को सच साबित करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि महंगाई पर काबू रखना राज्य सरकार का काम है। कांग्रेस का शासन बहुत कम राज्यों में है और गैर कांग्रेस शासित राज्य केंद्र सरकार का साथ नहीं दे रहे, इसलिए महंगाई पर काबू पाना कठिन हो रहा है। यदि इस तर्क में थोड़ा भी दम होता तो कम से कम कांग्रेस और कम्युनिस्ट शासित राज्यों में महंगाई की समस्या नहीं होती। पश्चिम बंगाल में तो खाने की वस्तुओं के लिए मारामारी हो रही है। राशन की दुकानों के बाहर दंगे हुए हैं।

मध्यमवर्ग के संपन्न होने का झूठा तर्क :

भारतीयों के खानपान को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो अब कहा है, उस कुतर्क को यूपीए सरकार के कृषिमंत्री बहुत पहले बोल चुके हैं। विगत 15 अप्रैल को संसद में यूपीए सरकार का बचाव करते हुए कृषिमंत्री शरद पवार ने कहा था, ''सरकार की नीतियों के कारण गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की क्रयशक्ति बढ़ी है और इसीलिए खाद्यान्न की मांग बढ़ रही है।''

भारत में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न खपत मात्र 178 किलोग्राम है, जो अमेरिका के खाद्यान्न खपत का केवल पांचवां भाग है। पोल्ट्री उत्पाद की प्रति व्यक्ति खपत 1.9 किलोग्राम है। विडंबना यह है कि शरद पवार का बयान ऐसे समय में आया है, जब हमारी 78 प्रतिशत आबादी प्रतिदिन बीस रुपए में गुजारा करने को अभिशप्त है। **सन् 1990–91 में अन्न की प्रति व्यक्ति खपत जहां 468 ग्राम थी, वह 2005–06 में घटकर मात्र 412 ग्राम रह गई है। दलहन की खपत मात्र 33 ग्राम है।**

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की जनवरी, 2008 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2005–06 में लगभग 19 प्रतिशत आबादी मात्र 12 रुपए प्रतिदिन से भी कम पर गुजारा कर रही है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में 44 प्रतिशत, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार में 29 से 34 प्रतिशत लोगों के पास हर रोज उपभोग पर व्यय करने के लिए 12 रुपए भी नहीं हैं। शहरी क्षेत्र में 22 प्रतिशत आबादी को जीवनयापन के लिए हर माह 580 रुपए से भी कम की राशि प्राप्त होती है यानि उनकी प्रतिदिन दैनिक उपभोग पर व्यय शक्ति 19 रुपए से अधिक नहीं है। उड़ीसा और उत्तरप्रदेश के शहरों में इतनी कम राशि में गुजारा करने वालों की आबादी 36 से 38 प्रतिशत है, जबकि बिहार में 56 प्रतिशत।

1990 से 2007 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर 1.9 प्रतिशत थी। इसी अवधि में खाद्यान्न उत्पादन की दर केवल 1.7 प्रतिशत रही। अर्थात् प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की खपत भारत में कम हुई है।

लगभग 65 करोड़ भारतीय सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर है। वर्ष 2005–06 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 19.7 प्रतिशत था, जो 2006–07 में घटकर 18.5 प्रतिशत पर आ गया। स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र में निर्भर आबादी के अनुपात में कमी नहीं आने से वहां औद्योगिक एवं सेवा के क्षेत्र में लगे लोगों की तुलना में गरीबी बढ़ती जा रही है। किसानों की आत्महत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस साल में अब तक करीब 200

किसानों की आत्महत्या की खबर है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के हाल के रिपोर्ट के अनुसार देश के करीब 4 करोड़ 30 लाख किसान कर्ज में डूबे हैं।

महंगाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें जिम्मेवार?

सरकार हमें यह भी मानने के लिए बाध्य करना चाहती है कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में वृद्धि हुई है, इसलिए हमें भी बढ़ी हुई कीमतों वाले दौर में रहने की आदत डालनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव से भारतीय बाजार के प्रभावी होने का तर्क तब उचित लगता, जब वैश्विक बाजार में भारत की महती भागीदार होती कृषि उत्पादों के निर्यात और आयात में भारत की विश्व बाजार में हिस्सेदारी नगण्य है। दूसरा लचर तर्क यह भी दिया जा रहा है कि भारत में कीमतें अभी भी विश्व के अन्य देशों से कम है। यदि सरकार भारत में विश्व स्तर की कीमतों को स्वाभाविक मानती है तो भारत में वेतन भी विश्वस्तरीय होना चाहिए। भारत के बहुसंख्य लोगों को बिलकुल निम्न स्तर के वेतन और आमदनी तथा विश्वस्तर की कीमत कभी भी साथ–साथ नहीं चल सकती।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव से यूपीए सरकार की चांदी :

संप्रग सरकार के कार्यकाल में आठ बार पेट्रोल–डीजल के दामों में वृद्धि की गई। राजग सरकार के कार्यकाल, मई, 2004 में पेट्रोल की कीमत 30.25 रुपए प्रति लीटर थी, जो आज करीब 47 रुपए प्रति लीटर है। तब 20.49 रुपए प्रति लीटर उपलब्ध डीजल की कीमत आज करीब 33 रुपए प्रति लीटर है। पेट्रोल–डीजल की कीमतों में वृद्धि कर संप्रग सरकार अपनी झोली तो भर रही है, किंतु आम आदमी कहां तक इस बोझ को सहन कर पाएगा? वर्ष 2004 में पेट्रोलियम क्षेत्र से राजस्व प्राप्ति 70,000 करोड़ थी। वर्ष 2007–08 में इस क्षेत्र से राजस्व वसूली 1,70,000 करोड़ हुई है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के मौकों को सरकार ने अपनी झोली भरने के अवसर के रूप में लिया है।

महंगाई के कारण

- एक कमजोर और प्रभावहीन प्रधानमंत्री के चलते सरकार उस रथ के समान है, जो योग्य सारथी के अभाव में अलग–अलग घोड़ों द्वारा भिन्न–भिन्न दिशा में खींचा जा रहा है। एक ओर तो वामपंथी यूपीए सरकार की टांग खींच रहे हैं तो दूसरी ओर स्वयं कांग्रेसी मंत्रियों में भी गहरा मतभेद है।

- महंगाई को लेकर सरकार के भिन्न मंत्रियों के विचार अलग–अलग हैं। प्रधानमंत्री बढ ़ती महंगाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार को प्रमुख कारण मानते हैं तो वित्तमंत्री लंबे समय से इसे थोड़े समय का संकट बताते आ रहे हैं। विज्ञान और तकनीकी मंत्री कपिल सिब्बल का कहना है कि महंगाई रोकने के लिए उसके पास जादू की छड़ी नहीं है। वित्तमंत्री पी. चिदंबरम और वाणिज्यमंत्री कमलनाथ के बीच सिर फुटव्वल के कारण महंगाई पर काबू पाने के लिए विगत 15 अप्रैल को आयोजित की गई बैठक रद्द करनी पड़ी थी।

- सरकार ने पिछले चार वर्षों में न तो वृहद अर्थव्यवस्था और ना ही अन्न के प्रबंधन पर उचित ध्यान दिया है। कृषि और आधारभूत ढांचे की उपेक्षा हुई है। सरकार की फिजूल

खर्चों के चलते राजकोषीय घाटा इस वर्ष सकूल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। इस तरह के घाटे से मुद्रास्फीति और तेजी बढ़ेगी।

यूपीए सरकार की विदाई आम आदमी के हित में :

आकाश छूती महंगाई के लिए यूपीए जितने कारणों का उल्लेख कर रही है, वस्तुतः ये सारी बहानेबाजी है। यूपीए सरकार का कार्यकाल आपसी झगड़ों और कम्युनिस्टों की ब्लैकमेलिंग के बीच तो गुजर ही रहा है, वह राजनीतिक वैरशोधन में भी समय और संसाधन व्यर्थ खर्च कर रही है। यह सरकार गंभीर अंतर्विरोधों से ग्रस्त है और महंगाई जैसी जटिल समस्या से लड़ने में अक्षम है। वित्त मंत्री स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि स्थिति चिंताजनक है और महंगाई से जल्दी राहत देना सरकार के लिए संभव नहीं है। महंगाई से निजात पाने के लिए आम आदमी को ही लड़ना होगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि यूपीए सरकार को जल्दी से बाहर का रास्ता दिखाए।

* * *